आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 02.10.2023 से 08.10.2023)

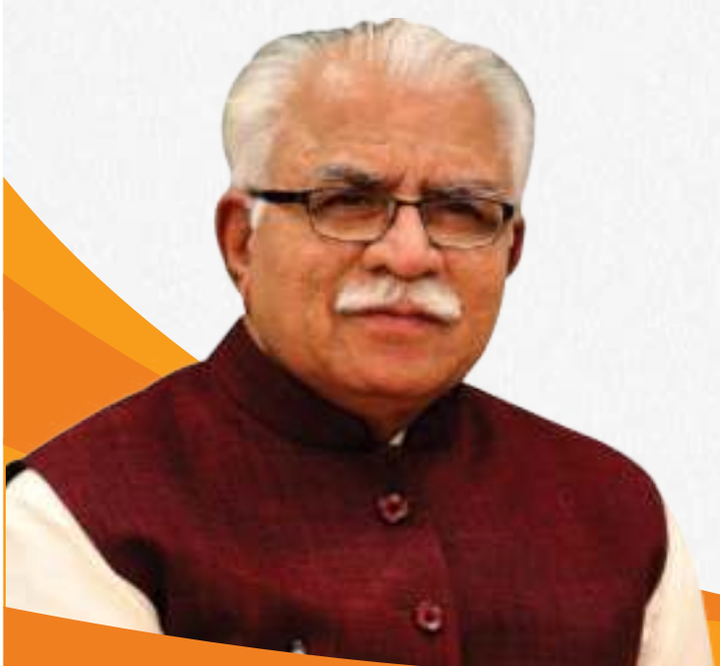

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

पंचकूला में आयोजित योग एवं आयुष सहायक प्रशिक्षण शिविर

(दिनांक 02.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पंचकूला में आयोजित योग एवं आयुष सहायक प्रशिक्षण शिविर को सम्बोधित कर कहा कि सरकार ने योग को नागरिकों की दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प किया है। इसीलिए प्रदेशभर में योगशालाएं स्थापित करने और 1000 आयुष सहायकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 882 आयुष योग सहायकों ने विभिन्न योगशालाओं में कार्यभार ग्रहण कर लिया है व शेष आयुष योग सहायकों की भर्ती का कार्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्रगति पर है। इसके दूसरे चरण में एक हजार और व्यामशालाओं पर कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों का आह्वान किया है कि वे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर एक स्वच्छए स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करने में अपना भरपूर योगदान दें। उन्होंने कहा कि योग करेगा इंडिया तभी तो निरोग रहेगा इंडिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज पूरे देश

में उत्सव का माहौल है। मानवता के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस पावन दिन पर योग को बढावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश में योग को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाने के उद्देश्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग को पूरे संसार में पहचान मिली है। उनके प्रयासों से विश्वभर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि योग टीचर की हर दिन मांग बढ़ रही है। इसलिए हमने गांवों में योगशालाएं खोलने और सहायक नियुक्ति करने का निर्णय लिया। अब ग्रामीण भारत में योग के प्रसार की जिम्मेदारी योग सहायकों के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि योगशालाओं में होने वाली योग गतिविधियों की निगरानी के लिए योग मानस पोर्टल व मोबाईल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस पर प्रतिदिन के कार्यों की रिर्पोट डाल सकते हैं। पोर्टल पर निजी संगठन एवं गैर सरकारी योग संस्थाओं के पंजीकरण के लिए भी योजना बनाई जा रही हैए ताकि उनके द्वारा की जाने वाली योग गतिविधियों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा सके।

उन्होंने कहा कि योग के महत्व को देखते हुए हरियाणा में नई पीढ़ी को योग प्रशिक्षण व योग साधना के लिए प्रेरित किया है। प्रदेश के स्कूलोंए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी योग सिखाया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2022.23 से कक्षा पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। झज्जर जिला

साप्ताहिक सूचना पत्र

के गांव देवरखाना में पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना गई है। उन्होंने कहा कि सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 6500 गांवों में व्यायामशालाएं खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए 1121 जगहों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 718 व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है व 273 योग एवं व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में जिला स्तर पर आयुष विंग स्थापित किये गए हैं जिनमें योग विषेशज्ञों की नियुक्ति की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सभी आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सैंटर में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। अब तक 386 आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सैंटर में अपग्रेड कर दिया गया है । इन आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सैंटर मे योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की जाएगी जो आमजन को योग से जीवन शैली में सुधार और बीमारियों से बचने

के तौर.तरीकों की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों को योग के साथ.साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के महत्व से भी अवगत करवाने का काम किया है। प्रदेश में सामाजिक समरसता कायम करने और संत–महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से उनकी जयंतियां राज्य स्तर पर मनाई जाती है। उसी प्रकार भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता को देखते हुए इन पद्धतियों के लिए भी विशेष दिवस निर्धारित किए हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उप–निरीक्षक राम लाल शर्मा को पर्वत श्रृंखला किलीमंजारों फतेह करने की शुभकामनाएं

(दिनांक 00.00.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सेक्टर–3 स्थित सरकारी आवास संत कबीर कुटीर से उप–निरीक्षक राम लाल शर्मा को राष्ट्रध्वज तिरंगा तथा ड्रग्स फ्री हरियाणा का झंडा देकर रवाना किया और चोटी फतेह करने की हरियाणा के लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि उप–निरीक्षक राम लाल शर्मा अब तक माउंट एवरेस्ट, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रास, नेपाल की माउंट आईलैंड पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुका है और समुद्र में साइकिल चलाने का भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जूनियर चौंबर ऑफ़ इंडिया के सांस्कृतिक आदान कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से वार्ता

(दिनांक 03.10.2023)

प्रभाव : देश की सांस्कृतिक नींव मजबूत करने के लिए जूनियर चौंबर ऑफ़ इंडिया द्वारा चलाये जा रहे सांस्कृतिक आदान –प्रदान कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों से आये जे.सी प्रतिनिधियों ने संत कबीर कुटीर में माननीय मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट की और हर क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति और उन्नति की भरपूर सराहना की। मंडल 10 के अध्यक्ष शैली चौधरी के नेतृत्व में तीन दिवसीय ष्म्हारा हरियाणाष् यात्रा कार्यक्रम में नौ राज्यों से आये सीनियर मेंबर एसोसिएशन सदस्य राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के

बाद मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। अपने आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल का भावभीना स्वागत किया और दक्षिण भारत से आए दल से ठेठ तमिल में बातचीत कर एक बार तो सब को हैरान कर दिया। उन्होंने संस्था के कार्यों और समाज में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की।

सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि जेसीआई इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन है जो देश के युवा पुरुषों और महिलाओं के नेतृत्व कौशल को विकसित कर उच्च चरित्र के श्रेष्ठ नागरिक बनाने के कार्य में लगी है और भारत के 26 राज्यों के सक्रिय है। यह अपने नेतृत्व और प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए भी जानी जाती है। सदस्यों ने बताया कि अपने दौरे में

उन्होंने हरियाणा को परंपरा और प्रगति का प्रदेश पाया जिसकी गूंज देश के अन्य राज्यों में भी पहुंच रही है, यही कारण है कि अपनी हरियाणा दर्शन यात्रा में वे प्रदेश के नेतृत्व से मुलाकात किये बिना रह नहीं पाए। राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप सब मिलकर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं।

जे.सी.आई इंडिया देश की युवा शक्ति को राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ने , समाज के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने का अनूठा और सराहनीय प्रयास कर रही है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से नशाखोरी, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कलंक को मिटाने में अधिक कारगर कार्य करने का आह्वान किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर दीक्षांत समारोह

(दिनांक 04.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर की दीक्षांत परेड समारोह में प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर का मनोबल बढ़ाते हुए उनसे आह्वान करते हुए कहा कि पुलिस केवल एक रोजगार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और देश के प्रति सेवा का सम्मान है। इसलिए पुलिसकर्मियों को सदैव अपनी वर्दी का सम्मान रखते हुए जन सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोबेशनर उप निरीक्षक बैच संख्या–20 में प्रथम रहे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार, द्वितीय स्थान पर रहे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मंजित और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर टीना को प्रशंसा पत्र व नगद पुरस्कार

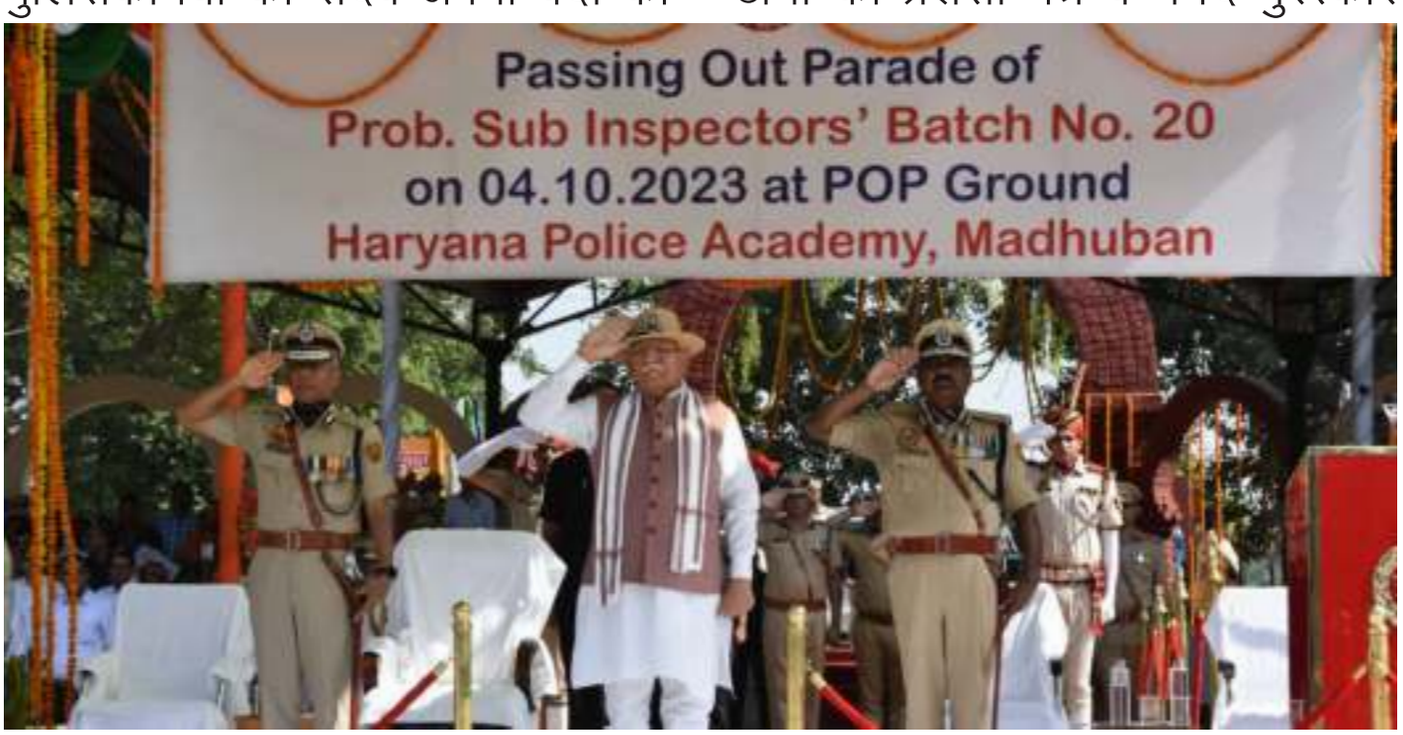

साप्ताहिक सूचना पत्र

देकर सम्मानित किया। आज के दीक्षांत समारोह में कुल 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर ने कर्तव्य परायणता की शपथ ली और जन सेवा के लिए स्वयं को समर्पित किया। इनमें 380 पुरुष तथा 61 महिलाएं शामिल हैं।

जिस प्रकार पुलिस अधिकारियों की पदोन्निति होती है और वर्दी पर स्टार बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार पुलिस थानों की भी स्टार रैंकिंग होनी चाहिए। उन्होंने सदैव जनता की सेवा को समर्पित रहने वाले पुलिसकर्मियों के कल्याणार्थ एक ओर कदम बढ़ाते हुए अनेक घोषणाएं की हैं। सभी पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों जैसे राशन मनी, वर्दी भत्ता, किट मेंटेनेंस अलाउंस, कमांडो की डाईट मनी में ढाई गुणा बढ़ोतरी की घोषणा की। राशन मनी को अब डाईट मनी के नाम से पुकारा जाएगा। साथ ही, उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की।

जैसे पहले डीएसपी को भर्ती के समय सिर्फ एक बार 5000 रुपये वर्दी भत्ता मिलता था, जोकि अब वर्ष में 10 हजार रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। उन्होंने कॉन्स्टेबल व हेड कॉन्स्टेबल को मिलने वाले कन्वेयंस अलाउंस को 120 रुपये

मासिक से बढ़ाकर 720 रुपये मासिक करने की घोषणा की, जोकि छरू गुना की वृद्धि है। साथ ही, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के लिए भी कन्वेंस भत्ता 1000 रुपये मासिक करने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत स्टाफ को विशेष भत्ते के रूप में बेसिक पे पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भत्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में बतौर प्रशिक्षण स्टाफ अस्थाई डयूटी पर आये हुए कर्मचारियों को भी मिलेगा।

शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने व गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने निरंतर कदम उठाए हैं। इसी दिशा में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हर पुलिस लाइन में ई–लाइब्रेरी खुलवाई जाए, ताकि पुलिसकर्मियों के बच्चे भी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। उन्होंने परेड में शामिल जवानों तथा उनके माता पिता को बधाई देते हुए कहा कि माता–पिता के सहयोग के बिना बच्चे पुलिस में शामिल होकर ऐसी

चुनौती भरे काम में इस प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सब का भी बहुत आभार। इन युवाओं ने जीवन अर्जन के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में जो रास्ता चुना है, वह सम्मानजनक है। आज के इस दीक्षांत समारोह को इस अकादमी का दीक्षांत समारोह माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में दीक्षांत समारोह इस अकादमी से अलग है, वह है समाज की अकादमी। और उस अकादमी को हमें अपने कार्यों से सफ़ल होकर बाहर निकलना होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ

(दिनांक 04.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के बच्छेर स्टेडियम में आयोजत पांच दिवसीय 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती कलस्टर का शुभारंभ करने उपरान्त उपस्थित पुलिस जवानों व विभिन्न प्रदेशों से आए पुलिस खिलाड़ियों को संबोधित कर कहा कि कुश्ती व कबड्डी प्रदेश के माट्टी के पारम्परिक खेल हैं, जिनको गांव–गांव में प्राचीन समय से खेला जाता है और ऐसे खेल हमें ऊर्जा, संस्कार व प्ररेणा देते हैं और इसी के चलते आज हरियाणा को खेलों की धरती व खेलों का हब के नाम से जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों व अर्ध–सैनिक बलों की 36 टीमों के 2561 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने देशभर से आए पुलिस खिलाड़ियों का हरियाणा की पावनधरा पर पहुंचने पर स्वागत व अभिनन्दन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

करने की बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा शारीरिक व्यायाम करने के साथ–साथ जो योग पद्धति को अपनाकर या खेल खेलकर अपने आपको फिट रखता है, वहीं हिट होता है। यही प्रदर्शन खिलाड़ियों की ओर से दिखता है। उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो उस विजय से न केवल उसे ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि खेल हर हरियाणवी की शान है और अपनी खेल प्रतिभा दिखाकर यहां के खिलाड़ियों ने सदैव देश व प्रदेश का मान बढ़ाया है। अभी हाल ही में चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भी देश को अब तक मिले 71 पदकों में से 19 हरियाणा के खिलाडियों ने जीते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को खेल, पुलिस, शिक्षा व ऊर्जा विभाग में नौकरियों में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूलों में हॉकी व मुक्केबाजी की नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 5 से 15 आयु वर्ग

के उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश विश्व का ऐसा प्रदेश है, जहां ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार ने निरंतर पहल की है। गांव, खण्ड, जिला व राज्य स्तरीय खेल स्टेडियमों का निर्माण किया गया है, जहां पर खिलाड़ी अभ्यास कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से आए सभी पुलिस खिलाड़ियों को कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हुआ महाभारत युद्ध का स्मृति चिन्ह अर्जुन रथ स्मृति के रूप में प्रदान करने की भी घोषणा की।

साप्ताहिक सूचना पत्र

एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का आभार

(दिनांक 04.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसवाईएल के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए न्यायालय का आभार जताया और पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने की मांग की। एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है और हरियाणा वासियों का हक है। वे आज के आदेश के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सभी प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अविलंब अमल करेगी।

उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह एसवाईएल के सर्वे का कार्य बिना देरी के पूर्ण करवाकर हरियाणा को वर्षों से लंबित उसका हक़ दिलवाने का कार्य करे। पंजाब अपने क्षेत्र में एसवाईएल कैनाल का निर्माण कार्य

पूरा न करके हरियाणा के हिस्से के लगभग 1.9 एमएएफ जल का उपयोग कर रहा है। हरियाणा को उसके हक का यह पानी मिलने से प्रदेश की 10.08 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, प्रदेश की प्यास बुझेगी व लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। इस पानी के मिलने से दक्षिणी–हरियाणा में जो भूजल स्तर काफी नीचे जा रहा है उसमें भी सुधार होगा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना देरी के एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल

(दिनांक 05.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों (अप्रैल–सितंबर 2023) में, राज्य का कुल कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 27,155 करोड़ रुपये की तुलना में 32,076 करोड़ रुपये हो गया है, जो 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस अवधि के दौरान, वैट का संग्रह 5,568 करोड़ रुपये था, आईजीएसटी निपटान और एसजीएसटी मुआवजे सहित एसजीएसटी संग्रह 20,670 करोड़ रुपये था, जो 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और उत्पाद शुल्क संग्रह 5,757 करोड़ रुपये था, जो 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जीएसटी कलेक्शन में हुई ये वृद्धि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को तो दर्शाती ही है, साथ ही यह राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है। वहीं इससे यह भी साबित होता है कि देश में एक देश–एक कर की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद कारगर है। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग के आधारभूत ढांचे को मजबूत एवं आधुनिक किया जा रहा है। विभाग में कर संग्रह के कार्यों में डिजिटलाइजेशन को अपनाया जा रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रेस वार्ता को संबोधित करना

(दिनांक 06.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 14 जिलों में 303 कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से नियमित करने की बड़ी घोषणा की है। इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन कॉलोनियों में 2,90,540 संपत्तियां बनी हुई हैं। इससे 10 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कुल 404 ऐसी नियमित की गई कॉलोनियों में सीवर लाइन, जलापूर्ति, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य विकास कार्यों विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियमित हो रही ये अधिसूचित कॉलोनियां कुल 5000 एकड़ जमीन पर बसी हुई हैं। इनमें नागरिक सुविधाएं तैयार करने और अन्य विकास कार्यों पर सरकार प्रति एकड़ 60 लाख रुपये खर्च करेगी। इससे यहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसी अनियमित कॉलोनियों की पोर्टल पर जानकारी मांगी थी, उनमें से 1507 कॉलोनी अभी शेष हैं। इनमें 936 शहरी

साप्ताहिक सूचना पत्र

स्थानीय निकाय की हैं और 571 कंट्रोल्ड एरिया में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प हैं कि 31 जनवरी, 2024 तक इन कॉलोनियों को भी नियमित कर दिया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तर पर उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम अधिसूचना की प्रगति की निगरानी करेगी।

उन्होंने कहा कि अनियमित कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) नहीं थी, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उस कॉलोनी के 5 लोग कॉलोनी के नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलोनी के नियमित होने के बाद उस आरडब्ल्यूए को रजिस्टर करवा लेंगे।

इसलिए कॉलोनियों के निवासियों से अपेक्षा है कि वे विकास शुल्क जमा करने और अपनी कॉलोनियों में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए सरकारी एजेंसियां के साथ समन्वय करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) का गठन करें। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कालोनियां भी हैं, जो नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र के बाहर बनी हैं। इनमें रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हमने उनकी पीड़ा को समझा और पहली बार ऐसी कालोनियों को भी नियमित किया गया है। इसके लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसी समिति की सिफारिश पर ऐसी कालोनियों को नियमित किया गया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत–प्रतिशत माफ करने की घोषणा

(दिनांक 06.10.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत–प्रतिशत माफ करने करने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। इसके अलावा, बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 15 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इस प्रकार संपत्ति मालिकों को छूट मिलने के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

सरकार ने प्रदेश की जनता को हाईवोल्टेज के खतरे से बचाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब घरों, फिरनी, पार्कों, तालाबों, स्कूलों आदि के ऊपर से गुजरने वाली 33,000 वोल्ट्स (केवी) और 11,000 वोल्ट्स (केवी) की बिजली लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ऐसी सभी लाइनों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे स्वीकृत प्रदान कर दी है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय–2010 (वर्तमान में 2023) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिजली के तारों और ऐसी लाइनों के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसे लाइन शिफ्ट कराने का पूरा खर्च वहन करना होता है। लेकिन सरकार ने लोगों की मांग पर उन्हें राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने जनकल्याण के मद्देनजर वर्ष 2016 में घरों के ऊपर से बिजली की लाइनें का अभियान चलाया था, जिस पर 112.17 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था। इसे सरकार ने वहन किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा में डेरों–ढाणियों में भी मिलेंगे बिजली कनेक्शन

(दिनांक 06.10.2023)

प्रभाव : हरियाणा के ग्रामीणों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली डेरों–ढाणियों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे पहले हमारी सरकार द्वारा 2016 में फिरनी से 1 किलोमीटर तक बनें 10 घरों को भी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया था।उन्होंने कहा कि यदि अभी भी कोई घर बचता है तो वे सोलर कनेक्शन ले सकते हैं। इस पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बेचिराग गांव, जिनकी फिरनी नहीं होती, उन्हें भी कनेक्शन दिए जाएंगे। बेचिराग गांव के लिए एक कनेक्शन रिजर्व करते हैं। लगभग 200–300 गांव ऐसे हैं।300 मीटर तक कोई सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। 300 मीटर के बाद एचटी, एलटी लाइन की जितनी लंबाई होगी, उसके खर्च का केवल 50 प्रतिशत पैसा उपभोक्ताओं से लिया जाएगा, शेष खर्च निगम वहन करेगा। पहले 150 मीटर के बाद कनेक्शन का सारा खर्च उपभोक्ता से लिया जाता था।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस विभाग को किसी किसान के खेत से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की चोरी होने पर थानों में बिना समय गवाएं एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर चोरी होने की स्थिति में नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए किसान को 50 प्रतिशत अब केवल 25 प्रतिशत राशि वहन करनी होगी। यदि ट्रांसफार्मर 10 साल से लगा है तो किसान केवल 10 प्रतिशत राशि देकर नया ट्रांसफार्मर लगवा सकता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सम्राट हेमचन्द्र विक्रमादित्य की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन

(दिनांक 07.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा भवन में सम्राट हेमचन्द्र विक्रमादित्य की स्मृति में स्मारक डाक टिकट विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान के साथ महान राष्ट्रभक्त एवं पानीपत की दूसरी लड़ाई के महानायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के दिल्ली राज्याभिषेक स्मृति दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में पानीपत तथा रेवाड़ी जिला में स्मारक बनाने की घोषणा की। संत महापुरूष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत दोनों जिलों में 4 से 5 एकड़ भूमि में यह स्मारक बनाए जाएंगे ताकि सम्राट हेमचन्द्र विक्रमादित्य की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन संत महापुरूषों ने समाज

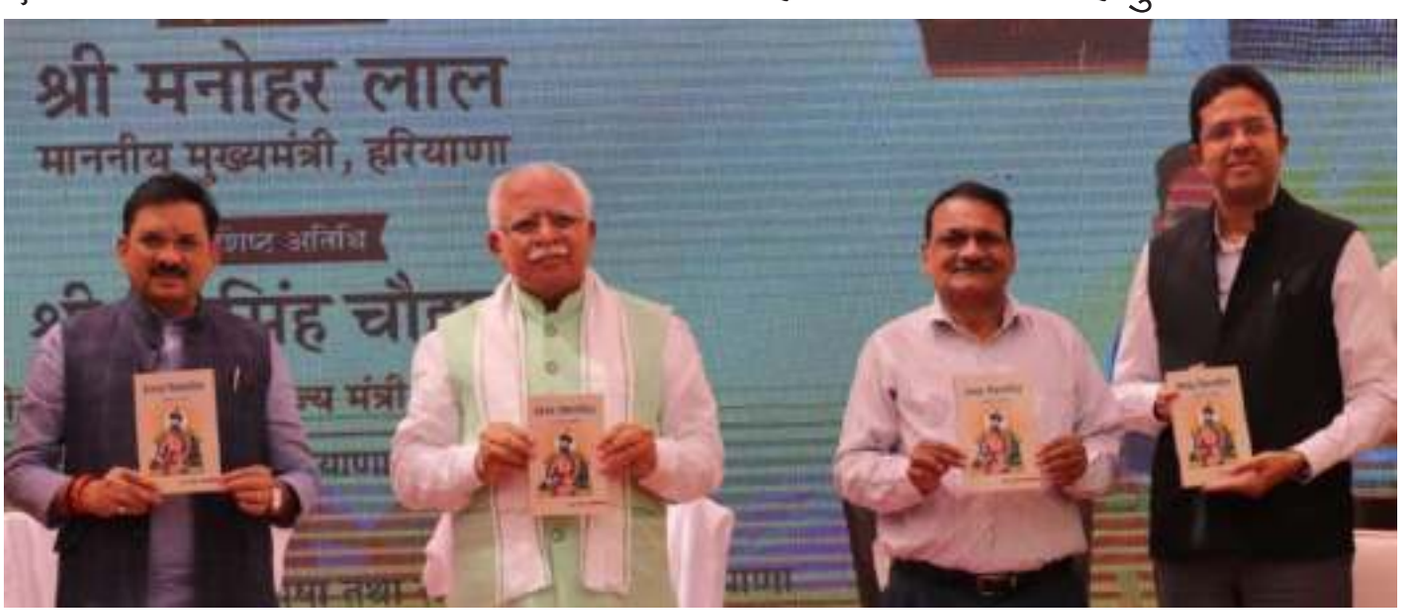

में जागृति लाने तथा देश की एकता, अखंडता व गौरव बढ़ाने का काम किया है, वर्तमान राज्य सरकार ने संत–महापुरूष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के माध्यम से उनके जीवन परिचय व शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जबकि पूर्व में ऐसी परम्परा जारी थी कि अपने या अपने पिता व दादा के नाम को आगे बढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि जो समाज एवं राष्ट्र अपने शहीदों का सम्मान करता है और सदैव उनके कल्याण के प्रति सजग रहता है वह समाज सदा समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हमें सदा अपने शहीदों को सम्मान के साथ याद रखना होगा। राष्ट्र की रक्षा, एकता एवं अखण्डता को कायम रखने के लिए हमारे वीर सैनिकों और देशभक्तों ने जो शहादत दी है। हमारा राष्ट्र उनका सदा ऋणी एवं कृतज्ञ रहेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था।

उन्होंने ही भले ही अल्प समय राज किया हो पर शताब्दियों के इस्लामी साम्राज्य के बीच उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व अवश्य ही भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पानीपत के पास गांव सौंदापुर में उनकी प्रतिमा आज भी लगी हुई है। ऐसे महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी हैं। ऐसी महान विभूतियों के आदर्श, सिद्धांत व शिक्षाएं मानव

साप्ताहिक सूचना पत्र

समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए हम संत–महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी उनके जीवन व कार्यों से प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त करे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं।

वे ऐसे महानायक थे, जिनकी एक साधारण व्यक्ति से सम्राट बनने तक की जीवन यात्रा हमें गर्व और गौरव से भर देती है। इससे हमारी नई पीढियों को जीवन में आगे बढ़ने, देशप्रेम और वीरता की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि संत महापुरूषों को सम्मान देने के लिए राज्य में अनेक शिक्षण संस्थानों

का नामकरण भी किया गया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधौला (पलवल), महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल, महाराणा प्रताप कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय करनाल आदि अनेक संस्थान प्रदेश में महापुरूषों के नाम पर खोले गए हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय संचार राज्यमंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि संत–महापुरुषों के विचारों को याद करने का सबसे अच्छा उदाहरण हरियाणा सरकार द्वारा पूरे देश में दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में क्रूर शासकों का महिमामंडन किया गया है, क्योंकि वर्ष 1947 से 1977 तक ऐसे मंत्री रहें, जिन्होंने सम्राट हेमू जैसे योद्धाओं की बहादुरी और शौर्य को इतिहास में जगह नहीं दी। उन्होंने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य महान योद्धा थे और उनके संघर्ष से आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकारों से संवाद

(दिनांक 07.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकारों से संवाद करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि आज से 50–60 साल पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या न के बराबर थी। आज महिलाओं ने पत्रकारिता में अपना खास मुकाम हासिल किया है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिला पत्रकारों का विशेष योगदान है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसवाईएल नहर बनाने पर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है और जल बंटवारा अलग विषय है। ऐसे में यह पंजाब सरकार का दायित्व है कि वह नहर का निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और अरविन्द केजरीवाल जब हरियाणा जाएंगे तो उन्हें एसवाईएल पर अपना रुख स्पष्ट

साप्ताहिक सूचना पत्र

करना होगा। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर पूछे गए सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा में बेटी बचाओ–बेटी पढाओ अभियान की सफलता रही है।

सरकार बनते ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे कहा था कि हरियाणा कम लिंगानुपात के चलते काफी बदनाम है ऐसे में सामाजिक जुडाव के साथ एक कार्यक्रम शुरू करे। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ–बेटी पढाओ अभियान की शुरूआत हुई और लिंगानुपात एक हजार लड़को के पीछे 871 से बढ़कर 927 तक पहुंचा। यह एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन हम अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में खाप पंचायतों और अन्य सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि हमने 8 साल में 72 नए कॉलेज खोले जिनमें महिला कॉलेजों की संख्या अधिक रही।

हमने लोकल बोडिज चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत रिप्रजेन्टेशन दिया। गांव में पढी लिखी पंचायतें चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी।प्रदेश में 30 से अधिक महिला थाने खोले गए। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 13

प्रतिशत हो गई जिसे हम 15 प्रतिशत कर रहे है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की बेटियां खेल और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने इसके लिए हिसार के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का जिक्र भी किया जिसमें विभिन्न विषयों में 20 में से 18 मेडल बेटियों ने हासिल किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्प को पुनः दोहराते हुए उन्होंने एक महिला पत्रकार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते।

यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जल्द लागू करने के एक सवाल के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसका समर्थन करते है। इससे समाज में सामंजस्य व समानता बढ़ेगी व राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह अभी हमारे प्रदेश में यह मामला पाइपलाइन में है और जब जरूरत होगी हम इसे लागू कर देंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि खर्च व समय की बचत के लिए यह बहुत आवश्यक है। जातीय जनगणना के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा कभी जातिगत राजनीति नहीं करती। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और हम हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर कार्य करते है।

संवाद के दौरान महिला पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके पंसदीदा खेल व शौक के बारे में पूछा तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कबड्डी मेरा पंसदीदा खेल रहा है और खेला भी हूँ। आज भी किसी राहगीरी के दौरान जब मौका मिलता है तो वह खिलाड़ियों के बीच जरूर जाते है। उन्होंने कहा कि खाली समय में सुडोकू हल करना मेरा शौक है इससे मुझे समस्याएं हल करने का बल मिलता है। संवाद के दौरान जब कुछ महिला पत्रकारों ने उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ कार्य करते हुए किसी किस्से के बारे में पूछा तो उन्होंने

कहा कि उनके साथ कार्य करते हुए सैकड़ों प्रसंग है। उन्होंने कहा कि एक बार जब वह 1996 में संगठन महामंत्री थे और श्री नरेन्द्र मोदी क्षेत्र के प्रभारी तो वह एक दिन सुबह–सुबह रोहतक कार्यालय में तीन बड़े डिब्बे लेकर पहुंचे। डिब्बे खोले तो उनमें कम्प्यूटर था जिसे यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियर से एसम्बल करवाया। इसके बाद उन्होंने इसी कम्प्यूटर पर सबसे पहले काम करना सीखा जो चमत्कार जैसा था और तकनीक से जुड़ने की प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल मुझे आज तक याद है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद

(दिनांक 07.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति से समाज और समाज से देश बनता है। इसके लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण आधार है और हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अभूतपूर्व कार्य किए हैं। राज्य में लगभग 14,000 विद्यालयों में सिविल कार्यों के साथ–साथ बच्चों के लिए डयूल डेस्क जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि समितियों की ओर से

बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव, या मांग आएगी, उसे हम पूरा करेंगे। संवाद के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसएमसी को 2 से 6 माह तक शिक्षक रखने का अधिकार देने पर सरकार विचार कर रही है। विस्तृत चर्चा के बाद इस संबंध में कुछ संशोधन करेंगे।उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 14,000 सरकारी स्कूल हैं।

इन स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं। इसके पीछे मूल भावना यह है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे आएं और स्कूल के विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि हमने स्कूल संचालन समितियों को सशक्त किया है और खरीद, निर्माण व संचालन के अधिकार दिए हैं। 25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों को करवाने की शक्ति मिलने के बाद समितियों ने सिविल कार्यों को इतनी कुशलता से सम्पन्न करवाया कि इनमें 15 से 20 प्रतिशत की बचत हुई है। यही नहीं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा तैयार भवन की गुणवत्ता भी ठेकेदार द्वारा करवाये गये कार्यों से बेहतर है। इसी प्रकार, ड्यूल डेस्क की खरीद का कार्य भी समितियों ने सराहनीय ढंग से किया है।

प्रदेश के स्कूलों में छात्र–अध्यापक अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही एमआईएस प्रणाली लेकर आ रही है । इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, उसके अनुसार अध्यापक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगर स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती तो अस्थायी तौर पर अध्यापकों की भर्ती कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। हालांकि इसको लागू करने की समयावधि 2030 तक है। लेकिन हमें इस लक्ष्य को पांच वर्ष पहले ही हासिल करना है और इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। इसमें शिक्षकों के

अलावा माता–पिता व अभिभावकों के सहयोग की भी जरूरत है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समितियां अध्यापकों की उपस्थिति एवं समय पालन के सम्बन्ध में अध्यापकों, माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करते रहें। इसी प्रकार स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की उपस्थिति, शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य, पढ़ाई की प्रगति की जानकारी लेते रहें। इसके लिए शिक्षकों व अभिभावकों की संयुक्त बैठक कर सकते हैं। स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करें ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के हर बच्चे का स्कूल में दाखिला हो और हर बच्चा स्कूल जाए। उन्होंने कहा कि पढाई बीच में छोड़ने वाले बच्चे को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसकी अथवा उसके माता–पिता की कोई समस्या है तो सामुदायिक आधार पर उसका निराकरण करें। उन्होंने कहा कि स्कूल में दोपहर के भोजन की गुणवत्ता से बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा है, इसलिए दोपहर के भोजन पर निगरानी रखें। समय–समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी करवाएं। स्कूल में खेल के मैदान, चारदीवारी, कमरों, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि के रख–रखाव पर ध्यान दें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण

(दिनांक 07.10.2023)

प्रभाव : विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) और समूह ए या समूह बी पदोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकारी पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का निर्धारण करेंगे।

यदि प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है तो पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होने पर कमी को दूर किया जाएगा। पदोन्नति के माध्यम से भरे गए ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति का तरीका जो भी हो, प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा।

कोई प्रत्यावर्तन नहीं– नॉन–एससी कर्मचारी, जिन्हें पहले ही ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन कमी को दूर तब किया जाएगा जब पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होगा।

पदोन्नति से कोई वंचित नहीं– अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पूरी हो गई हो।

रोस्टर अंक– सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती हेतु रोस्टर अंक लागू होंगे। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्वाइंट या प्रतिस्थापन सिद्धांत के आवेदन के लिए दिशानिर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।

नॉन–एससी पदोन्नति– यदि कोई पात्र एससी कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है। अनुसूचित जाति कर्मचारी को पात्र होने

पर एक अतिरिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा।

परिणाम स्वरूप वरिष्ठता– पदोन्नति में आरक्षण से पदोन्नति पद पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

एसीपी वेतन स्तर– जहां संवर्ग में प्रतिशत–आधारित मानदंड मौजूद हैं, वहां एसीपी वेतन स्तर देने के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा।

जरनैल सिंह बैच के मामले– चूंकि जरनैल सिंह बैच के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इन निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए सभी पदोन्नति आदेश इन मामलों में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अगले आदेश के अधीन होंगे।

कड़ाई से अनुपालन– नियुक्ति प्राधिकारी इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही पदोन्नति आदेश जारी करेगा।

प्रभावी तिथि– यह निर्देश तुरंत प्रभावी होगा और हरियाणा सरकार के तहत सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्देश वापस ले लिए गए हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

यमुनानगर में जन संवाद कार्यक्रम

(दिनांक 08.10.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर के प्लाईवुड फैक्टरियों के संचालकों की लम्बे समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए लक्कड़ की खरीद पर लगने वाली 2 प्रतिशत मार्किट फीस को घटाकर 1 प्रतिशत किया है। इससे प्लाईवुड फैक्टरियों के संचालकों को प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ होगा। कोरोना काल के बाद बोर्ड व्यापारी व्यापार में मंदी की शिकायत कर रहे थे, इसी को गम्भीरता से लेते हुए, राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर के दशहरा ग्राऊंड में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत वह जनता के बीच में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं व उनका निवारण भी करते है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में ऐसी पुरानी कालोनी जिसका कुछ क्षेत्र वैध हो गया था और कुछ क्षेत्र अवैध रह गया है, ऐसी कालोनियों का

सर्वे करवाया जाएगा और 4–5 महीने में ऐसी कॉलोनियों के क्षेत्र को भी वैध किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार, जिनका व्यवसाय के हिसाब से बिजली का बिल ज्यादा आता है, उन परिवारों का फिजिकल सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे के हिसाब से जो भी इन परिवारों को सुविधा संभव होगी उन्हें दी जाएगी। ऐसे परिवारों में ऑटो चलाने वाला, धोबी, प्रेस करने वाला, नाई, बढ़ाई का काम करने वाले परिवारों को भी जोड़ा जाएगा।माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यमुनानगर जिले में बीपीएल के दिसम्बर, 2022 में 55693 कार्ड थे जबकि अब 71388 कार्ड बने हैं। उन्होंने 7 महीनों में करीब 16 हजार कार्ड नए बने हैं।

उन्होंने कहा कि पहले एएवाई कार्ड धारको को 2 लीटर सरसो का तेल मिलता था, अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी बीपीएल कार्ड धारको को 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। उन्होंने बीपीएल परिवार की बिजली के बिल की 12 हजार प्रति माह की स्लैब को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकतर जन सुविधाएं ऑनलाईन कर दी हैं और इनसे

साप्ताहिक सूचना पत्र

सम्बंधित जानकारी भी मोबाइल पर दी जा रही है। प्रदेश में जिन परिवारों के पास मोबाइल नहीं है ऐसे परिवारों का सर्वे करवाया जाएगा और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इन परिवारों को भी मोबाइल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि ऐसे परिवार भी ऑनलाईन सुविधाओं का लाभ ले सकें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जिले में दिव्यांग व्यक्तिओं को सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 48 हजार 715 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है जिसमें से 17 हजार 383 लोगों ने आयुष्मान के तहत उपचार करवाया है। इस उपचार के माध्यम से 44 करोड़ 78 लाख रुपये का खर्च आया है इन परिवारों को एक भी रुपया अपने पास से नहीं देना पड़ा। जन संवाद कार्यक्रम में इस योजना का लाभ लेने वालों लाभार्थियों ने माननीय

मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में 15 सडक़ों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई, जिनमें से 8 सडक़ो पर निर्माण कार्य चल रहा है और 7 का शीघ्र ही टैंडर हो जाएगा।माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 साल हो गई है और आय 3 लाख से कम है, संवाद के दौरान 11 लोगों की तुरंत पैंशन बनवाई गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पैंशन का प्रमाण पत्र सौंपा और बधाई दी।